



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/ पौष 26, 1938

No. 467]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 26, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 दिसम्बर, 2016

सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य.—पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार अपने पत्र संख्या डब्ल्यू टीसी-15025/5/2012-आईडब्ल्यूटी (खंड-III)(भाग) दिनांक 25 नवंबर, 2016 के अनुसरण में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)/तटीय पोत परिवहन करार भारत और बंगलादेश जनतंत्र के मध्य हुए करार के अनुसार बंगला देश जनतंत्र के पोतों से, पत्तन देयता और अन्य प्रभारों के नियमितिकरण के लिए, सभी पत्तन न्यासों के दरमानों में शामिल करने के लिए प्रावधान, संलग्न आदेशानुसार अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य

आदेश

(दिसंबर 2016 के 16वें दिन पारित)

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या डब्ल्यूटीसी-15025/5/2012-आईडब्ल्यूटी (खंड-III)(भाग) दिनांक 25 नवंबर, 2016 के द्वारा अपना निर्णय संप्रेषित किया है कि सभी महापत्तन, बंगलादेश जनतंत्र के पोतों के भारत में प्रवेश हेतु पत्तन देयता और अन्य प्रभार, दोनों के लिए, दोनों देशों के मध्य हुए तटीय पोत परिवहन करार के तहत, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के खंड 6 को लागू करने के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करेंगे।

2. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या डब्ल्यू टीसी-15025/5/2012-आईडब्ल्यूटी (खंड-III)(भाग) दिनांक 25 नवंबर, 2016 की विषय-वस्तु इस प्रकार है :

- (i) भारत बंगलादेश तटीय पोत परिवहन करार (अधोलिखित) के तहत मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी के खंड 6 के अनुसार, बंगलादेश से भारत आने वाले पोतों को, भारत एवं बंगलादेश के मध्य हुए तटीय पोत परिवहन करार के तहत विदेशगामी(एफजी)पोत नहीं माना जाना चाहिए।

"6. पत्तन एवं अन्य प्रभार :

6.1. पत्तन देयता अंतर-देशीय और अन्य देशों के साथ व्यापार में संलग्न पोतों पर किसी भी देश में पत्तन प्रभार, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही लगाया जा सकता है जिसे तटीय पोत परिवहन और न कि विदेशगामी (एफजी) पोत के तौर पर माना जाएगा।

6.2. किसी भी देश में सक्षम नौवहन प्राधिकारी अन्य देश के पोत पर संरक्षण, पॉयलटेज और अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए अन्य स्थानीय पोतों के समतुल्य प्रभार भी लगा सकते हैं। ये प्रभार, देशज तटीय पोत परिवहन में पोतों पर लागू पोत के कार्गो वहन की क्षमता के संदर्भ के अनुसार ही निर्धारित किए जाएंगे "

- (ii) तथापि, मंत्रालय के समक्ष ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिनमें बंगलादेश जनतंत्र से संबंधित पोतों पर प्रारंभ में भारतीय पत्तन में प्रवेश करने पर भारत और बंगलादेश जनतंत्र के मध्य हुए करार के तहत 'विदेशगामी पोत' के समान 'पोत व अन्य प्रभार' लगाए गए और बाद में इस मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अधिक प्रभारित राशि, संबंधित महापत्तन के बोर्ड के अनुमोदन से, पोत के स्वामी को लौटा दी गई।

3. यह प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय के कथित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सभी महापत्तन न्यासों को अपने दरमानों में यह प्रावधान शामिल करने के निदेश जारी करता है कि :

- " (i) (क) भारत बंगला देश तटीय पोत परिवहन करार (अधोलिखित) के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के खंड 6 के अनुसार, बंगलादेश से भारत आने वाले पोतों को, भारत एवं बंगलादेश के मध्य हुए तटीय पोत परिवहन करार के तहत विदेशगामी (एफजी) पोत नहीं माना जाना चाहिए।

(ख)" पत्तन एवं अन्य प्रभार :

- (i) बंगला देश जनतंत्र के पोतों के दोनों देशों मध्य हुए तटीय पोत परिवहन करार के तहत भारत में भारत में प्रवेश करने वाले तथा अंतर-देशीय व्यापार में संलग्न पोतों पर महापत्तन न्यासों द्वारा प्रभार लगाने के लिए उन्हें देशज (डोमेस्टिक) पोत न कि विदेशगामी (एफजी) पोत के तौर पर माना जाएगा।
- (ii) महापत्तन न्यास, बंगलादेश जनतंत्र के पोतों पर संरक्षण, पॉयलटेज और अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए अन्य तटीय पोतों के समतुल्य प्रभार भी, अन्य देश के पोत पर लगा सकेंगे। ये प्रभार, तटीय पोत परिवहन में देशज पोतों पर लागू पोत के कार्गो वहन की क्षमता के संदर्भ के अनुसार ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. दरमानों में उपर्युक्त संशोधन, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा सभी महापत्तन न्यासों के लिए जारी किए गए निदेशों की तिथि अर्थात् 25 नवंबर, 2016 से प्रभावी माना जाएगा। सभी महापत्तन न्यासों को निदेश दिए जाते हैं कि वे अपने दरमान, तदनुसार संशोधित कर लें।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[ विज्ञापन-III/4/असा./355/16]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 19th December, 2016

**No.TAMP/4/2004-Genl.**—In pursuance to the Ministry of Shipping, Government of India, letter No.WTC-15025/5/2012-IWT (Vol. III) (Pt) dated 25 November, 2016 and in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies provisions for incorporation in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts, regarding Regulation of port dues and other charges from the vessels of Republic of Bangladesh as per Standard Operating Procedure (SOP)/ Coastal Shipping Agreement between India and the Republic of Bangladesh, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No. TAMP/4/2004-Genl.**ORDER**

(Passed on this 16th day of December, 2016)

The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.WTC-15025/5/2012-IWT (Vol. III) (Pt) dated 25 November, 2016 has conveyed its decision that, all the major ports should seek approval of the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) for adoption of the clause 6 of the Standard Operating Procedure (SOP) while levying port dues and other charges for entry of vessels of the Republic of Bangladesh into India under the Coastal Shipping Agreement between the two countries.

2. The contents of MOS letter No.WTC-15025/5/2012-IWT (Vol. III) (Pt) dated 25 November, 2016, are given below:

- (i) As per Clause 6 of the Standard Operating Procedure (SOP) for operation of Indo-Bangladesh Coastal Shipping Agreement (given below), the vessels entering into India from Bangladesh under the Coastal Shipping Agreement between India and Bangladesh are not to be treated as foreign going (FG) vessels.

“6. Port and other charges:

6.1 Port dues may be levied by the Competent Maritime Authorities in either country on the vessels belonging to the other country and engaged in inter country trade, which will be treated as domestic vessel engaged in coastal shipping and not as Foreign Going (FG) vessels.

6.2 The Competent Maritime Authorities in either country may also levy on the vessels of the other country charges for conservancy, pilotage and other specific services at par with those charged from the local vessels. The charges will be determined with reference to cargo carrying capacity of the vessels, as applicable to domestic vessel engaged in coastal shipping.”

- (ii) Instances have, however, come to the notice of this Ministry where a vessel belonging to the Republic of Bangladesh was initially levied port and other charges as for Foreign Going (FG) vessels on its entry to Indian Port under Coastal Shipping Agreement between India and Bangladesh. On subsequent intervention of this Ministry, the amount charged in excess was refunded to the owner of the vessel which approval of the Board of the said Major Port.

3. In view of the said direction of the MOS, this Authority directs all the Major Port Trusts to incorporate the following provision in their Scale of Rates:-

- “(i) (a) As per Clause 6 of the Standard Operating Procedure (SOP) for operation of Indo-Bangladesh Coastal Shipping Agreement (given below), the vessels entering into India from Bangladesh under the Coastal Shipping Agreement between India and Bangladesh are not to be treated as foreign going (FG) vessels.

(b) Port and other charges

- (i) Port dues to be levied by the Major Port Trust on the entry of vessels of the Republic of Bangladesh into India under the Coastal Shipping Agreement between the two countries and engaged in inter country trade, will be treated as domestic vessel engaged in coastal shipping and not as Foreign Going (FG) vessels.

- (ii) The Major Port Trust shall also on the vessels of the Republic of Bangladesh levy charges for conservancy, pilotage and other specific services at par with those charged from the coastal vessels. The charges will be determined with reference to cargo carrying capacity of the vessels, as applicable to coastal vessel engaged in coastal shipping.”

4. The above amendment in the SOR will be effective from the date the MOS issued the direction to all the Major Port Trusts i.e. from 25 November, 2016. All the Major Port Trusts are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty. /355/16]